

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ०प्र० लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक : 27 अगस्त, 2012

विषय:- तेरहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत राज्य विशिष्ट अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में वाराणसी शहर में अग्निशमन एवं आपात कालीन सेवाओं के उन्नयन हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्य पाल महोदय वित्तीय वर्ष 2012-13 में, तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वाराणसी शहर में अग्निशमन एवं आपात कालीन सेवाओं के उन्नयन के सम्बन्ध में वर्ष 2011-15 हेतु संस्तुत रुपये-2000.00 लाख के सापेक्ष उत्तर प्रदेश फायर सर्विस मुख्यालय, लखनऊ के पत्रांक-22-एफएस(टी)-208-2011 दिनांक 23.11.11 द्वारा उपलब्ध करायी गयी कार्ययोजना अन्तर्गत वर्ष 2011-12 की कार्य योजना में उल्लिखित कार्यों को कराने हेतु प्रयोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित धनराशि रुपये-455.72 लाख (रुपये चार करोड़ पचपन लाख बहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रु०455.72 लाख की धनराशि अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश फायर सर्विस मुख्यालय, लखनऊ को अवमुक्त करने हेतु निम्नलिखित कार्य विवरण शर्तों के अधीन आप के निर्वर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :

क्र	मद	प्रस्तावित लागत	प्रयोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित धनराशि
1	सिविल सम्बन्धी कार्य	372.13	329.97
2	अग्निशमन हेतु इक्यूपमेन्ट/वाहनों का कय	125.75	125.75
	योग-	497.88	455.72

- उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि आपके निर्वर्तन पर इस शर्त के साथ रखी जा रही है कि योजनान्तर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि 13 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत नियमानुसार अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश फायर सर्विस मुख्यालय, लखनऊ को आवंटित की जायेगी।
- स्वीकृत अनुदान का उपयोग भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या-एफ.11(9) एफसीडी/2010 दिनांक 26.04.2011 (छायाप्रति संलग्न) की गाइडलाइन्स के अनुसार ही किया जायेगा।
- वाहन/उपकरणों का कय डी.जी.एण्ड एस.एन.डी. के अनुसार किया जायेगा।
- स्वीकृत धनराशि का आहरण अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश फायर सर्विस मुख्यालय, लखनऊ द्वारा जनपद कोषागार से किया जायेगा। स्वीकृत की

- जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिए जिलाधिकारी के हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी।
5. स्वीकृत धनराशि को एक मुश्त आहरित कर किसी बैंक/डाकघर/पीएलए व डिपोजिट खाते में नहीं रखा जायेगा। धनराशि का कोषागार से आहरण कार्य की आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
 6. अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश फायर सर्विस मुख्यालय, लखनऊ द्वारा धनराशि की आहरण की सूचना बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित निदेशक, स्थानीय निकाय उनसे प्राप्त करेंगे तथा उसकी सूचना शासन के वित्त विभाग व नगर विकास विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
 7. टेण्डर की कार्यवाही कार्य योजना में उल्लिखित कार्यों हेतु ही नियमानुसार की जायेगी।
 8. इस अनुदान के लेखों का रख-रखाव नियमानुसार संबंधित निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 एवं कार्यदायी इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। इस अनुदान के उपयोग एवं सम्प्रेषण की प्रणाली निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
 9. 13 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत संस्तुत अनुदान राशि का उपयोग निर्धारित स्कीमों के अन्तर्गत लिए जाने से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराये जायेगे। लेखों का रख रखाव तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र/व्यय विवरण को सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2005 के अनुसार उपलब्ध कराया जायेगा। तत्संबंधी प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र यथा शीघ्र भारत सरकार को वित्त विभाग के माध्यम से शासन द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
 10. विशेष पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश फायर सर्विस मुख्यालय, लखनऊ द्वारा प्रेषित कार्य योजना पर उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति का अनुमोदन प्राप्त है। इसलिए कार्य योजना में उल्लिखित कार्यों के अतिरिक्त किसी भी दशा में अन्य कार्य नहीं कराये जायेगे। परियोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाना भी सुनिश्चित किया जाय।
 11. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों को समयबद्ध रूप से व पूर्ण गुणवत्ता के साथ कराये जाने का दायित्व निकाय/कार्यदायी संस्था तथा जिलाधिकारी का होगा। धनराशि का भुगतान कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बाद ही किया जायेगा।
 12. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्यय अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-60-अन्य शहरी विकास योजनाएं-191 नगर निगमों को सहायता-04-तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों का कार्यान्वयन-0401-वाराणसी की अवसंरचना सुधार-35 पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या:यू.ओ. ई-81002-...../दस/12, दिनांक-09/08/12 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

25/8/2012
(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या- 865 (1)/नौ-9-12तददिनांक 27 अगस्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (रिपोर्ट ब्रान्च) उ०प्र० इलाहाबाद / प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
3. मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी / कोषाधिकारी, वाराणसी।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, निधि लेखा परीक्षा, उ०प्र० इलाहाबाद।
5. नगर आयुक्त नगर निगम, वाराणसी।
6. अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश फायर सर्विस मुख्यालय, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग / वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

५

No. F 11(9)/FCD/2010
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
Finance Commission Division

Block No. XI, 5th Floor, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi, 26th April, 2011

To
The Chief Secretary,
Government of
(All State Governments)

Subject: Implementation of recommendation of Thirteenth Finance Commission- issue of guidelines for release and utilisation of grant-in-aid for **State Specific Needs** recommended by Thirteenth Finance Commission.

Dear Sir/Madam,

The recommendations of Thirteenth Finance Commission for the award period 2010-15 include, inter-alia, release of grant-in-aid to the State Governments for **State Specific Needs**. State Governments are advised to utilise the grant in conformity with the recommendations of the Commission contained in paras 12.115 to 12.326 of the report of FC-XIII (Vol. I).

I am enclosing herewith the guidelines for release and utilization of grant-in-aid for State Specific Needs as recommended by the Thirteenth Finance Commission for information and necessary action. These guidelines are also accessible on this Ministry's website:
<http://www.finmin.nic.in/TFC/guidelines.asp>

Yours faithfully,

Encl.: As above

(Alok Chandra)
Director (FCD)
Tel: 24360647
Fax: 24360174

Email: alok.chandra@nic.in

Copy with a copy of the guidelines to:-
Principal Secretary (Finance), Government of
(All State Governments)

F. No. 11(9)/2010-FCD
Ministry of Finance
Department of Expenditure
Finance Commission Division

11th Block, 5th Floor,
CGO Complex, Lodi Road,
New Delhi- 110003.
Dated: 26th April 2011

Subject: Implementation of recommendation of Thirteenth Finance Commission (FC-XIII) regarding release and use of grant-in-aid for **State Specific Needs**.

Recognising that States have specific issues and local needs, the Thirteenth Finance Commission (FC-XIII) has recommended grants-in-aid, amounting to Rs.27945 crore, to address state specific needs during its award period, 2010-15. The recommendations have been accepted along with the conditions stipulated by FC-XIII.

2. State specific grants (SSG) are available from 2011-12 onwards to States, except for three grants already released in 2010-11. State-wise and year-wise allocations are contained in table 12.6 of the report of FC-XIII (Vol.I), reproduced in **Annex I** to this letter. A perusal of paragraphs 12.118 to 12.323 in Vol.I of FC-XIII's report clarifies the objectives and contours of each recommended grant. These grants are to be accounted as plan resources in the States' plans.

Objectives

3. The SSGs are focussed on the needs to:

- i) address the specific needs of marginal areas and marginal groups within States;
- ii) provide infrastructure to alleviate some of the problems faced by the local population in blocks and tehsils along the international borders;
- iii) protect historical monuments, archaeological sites and heritage buildings, which are not with the Archaeological Survey of India (ASI);
- iv) provide safe drinking water, especially in regions afflicted with arsenic, salinity and fluoride related problems;

- v) fill gaps in critical infrastructure for health, including care for children;
- vi) set up and strength skill-building institutions to help provide employable skills; and
- vii) meet the training requirements of police personnel at various levels.

Conditions of release

4. The release of SSGs is subject to the following pre-conditions:

- i) States' enactment/amendment their FRBM Acts, incorporating the targets (regarding deficit and debt reduction) laid down by FC-XIII (para-9.82 of report), as communicated vide Ministry of Finance letter No.1(1)/FRU-2010 dated 14.01.2011. SSGs will be liable to be withheld to a State if it fails to comply with the requirements relating to FRBM roadmap.
- ii) Upon GST being introduced, if a State fails to abide by an agreement that it has entered into on GST, SSGs will become liable to be withheld for the period during which a State is in violation of the agreement. If a State is in violation only for a part of a year, the SSGs will be liable to be reduced pro-rata (para-5.52).
- iii) Funds from any of the SSGs are not to be used for land acquisition. Wherever land is required for the project being funded, such land will need to be made available by the State Government.

Phasing of release of SSGs

5.

- i) The first instalment will be released on submission of the working plan, approved by the State High Level Committee (HLMC) chaired by the Chief Secretary. A copy of the approved working plan needs to be sent to the Department of Expenditure and each of the line Ministries concerned. Release of subsequent instalment will be on receipt of a utilization certificate as per GFR 2005 in respect of any previous release from this grant.
- ii) An indicative phasing of the state-specific grants is given in Annex-I. Grants would be released in four instalments during the award period 2011-15 as in Annex-I. For projects involving construction, 10% of the grant will be withheld, and released on submission of a completion certificate (CC). States are requested to ensure that CCs are

submitted well before March, 2015 so that final releases can be made within the award period of FC-XIII (2010-15).

- iii) If a State intends to have phasing of grants different from that given in Annex-I, this may be communicated to Ministry of Finance, with justification, along with a copy of the minutes of the relevant meeting of the HLMC, referred to in para 6 below. While proposing revised phasing, States are requested to take into account their absorptive capacities. In case any revised phasing entails release of more than 25% of the grant in 2011-12, it may be possible to release the additional amount after provision of a supplementary allocation, in January, 2012.
- iv) Activities undertaken from funding under this grant, in conformity with the approved working plan, will be complementary to those under existing schemes/programs of the Central Govt. Any overlap of activities under existing schemes/programs must be avoided. A copy of this communication is being endorsed to the concerned central line Ministries, to facilitate dovetailing of benefits under their schemes with those intended from the SSGs.
- v) Accounts shall be maintained and utilization certificates provided as applicable for Grants-in-aid under the General Finance Rules (GFR 2005).

Monitoring agency in the State

6. Every State shall constitute a High Level Monitoring Committee (HLMC) for approval of the State's working plan and monitoring of utilisation of SSGs in accordance with this plan. The HLMC shall be headed by the Chief Secretary to the State Government and will include the Finance Secretary and Secretaries of Departments concerned as members. The HLMC shall meet on a quarterly basis during the award period. Minutes of HLMC meetings shall be provided to the Department of Expenditure (Finance Commission Division), Ministry of Finance and the line Ministry concerned in the Government of India.

Monitoring agency in Union Government

7. The broad sector-wise segregation of the grants recommended by FC-XIII for meeting State Specific Needs is summarized in **Annex-II**. A perusal of

paragraphs 12.118 to 12.323 in Vol.I of FC-XIII's report is essential to clarify the objectives and contours of each recommended grant. Review Committees will be chaired, where feasible, by Secretaries of line Ministries/Department as suggested in Annex-II. These Review Committees will include a representative, inter-alia, from the Ministry of Finance (Department of Expenditure). The Committees shall review working plans of States to ensure complementarity of activities to be undertaken from this grant and those under existing schemes/programs of the Central Govt., to avoid duplication of expenditure, and monitor the progress of the implementation of the grants on a regular basis. Wherever it is deemed appropriate by the line Ministry concerned, the SSGs may be monitored by existing Committees focussed on similar projects or schemes.

Audit by the Controller and Auditor General

8. The Comptroller and Auditor General of India would audit the release and use of the grants-in-aid.

(Alok Chandra)
Director (FCD)

Tel.: 011-24360647

Fax: 011-24360174

Email: alok.chandra@nic.in

Sl. No	Name of State	State Specific Needs					(Rs in Crore)
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2010-15
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Andhra Pradesh	20	312.50	312.50	312.50	312.50	1270
2	Arunachal Pradesh		75.00	75.00	75.00	75.00	300
3	Assam		150.00	150.00	150.00	150.00	600
4	Bihar		461.25	461.25	461.25	461.25	1845
5	Chhattisgarh		320.25	320.25	320.25	320.25	1281
6	Goa		50.00	50.00	50.00	50.00	200
7	Gujarat		325.00	325.00	325.00	325.00	1300
8	Haryana		250.00	250.00	250.00	250.00	1000
9	Himachal Pradesh		87.50	87.50	87.50	87.50	350
10	Jammu & Kashmir	1000	87.50	87.50	87.50	87.50	1350
11	Jharkhand		356.25	356.25	356.25	356.25	1425
12	Karnataka		325.00	325.00	325.00	325.00	1300
13	Kerala		375.00	375.00	375.00	375.00	1500
14	Madhya Pradesh		307.75	307.75	307.75	307.75	1231
15	Maharashtra		308.75	308.75	308.75	308.75	1235
16	Manipur		75.25	75.25	75.25	75.25	301
17	Meghalaya		62.50	62.50	62.50	62.50	250
18	Mizoram		62.50	62.50	62.50	62.50	250
19	Nagaland		62.50	62.50	62.50	62.50	250
20	Orissa		436.25	436.25	436.25	436.25	1745
21	Punjab	30	362.50	362.50	362.50	362.50	1480
22	Rajasthan		300.00	300.00	300.00	300.00	1200
23	Sikkim		100.00	100.00	100.00	100.00	400
24	Tamil Nadu		325.00	325.00	325.00	325.00	1300
25	Tripura		125.00	125.00	125.00	125.00	500
26	Uttar Pradesh		419.75	419.75	419.75	419.75	1679
27	Uttarakhand		175.00	175.00	175.00	175.00	700
28	West Bengal		425.75	425.75	425.75	425.75	1703
	Total	1050	6723.75	6723.75	6723.75	6723.75	27945

Source: Table 12.6, FC-XIII report, Vol.1

Grants recommended by the Thirteenth Finance Commission (FC-XIII) for Police Up-gradation, Housing, Training, Prison and Fire Services (Line Ministry – Ministry of Home Affairs (MHA))

Review Committee in MHA

(Rs in Crore)

Sl. No.	Name of State	Sector	Amount	Brief description of scheme
1	Andhra Pradesh	Police Training	113.00	(i) Rs. 13.0 crore to strengthen the training facilities at Premavathipet Hyderabad and at the regional headquarters in Vishakapatnam. (ii) Rs. 100 cr for up-gradation of the Police Training College at Warangal, shifting of the old Police Training College and Amberpat to Medak and establishing a new Police Training college at Karimnagar.
		Prisons	90.00	Construction of Prisons to augment capacity.
		Fire	17.00	To strengthen Fire & Emergency services by providing essential equipment to convert the service into a multi-hazard response unit.
2	Arunachal Pradesh	Police Housing	70.00	Construction of police stations with lock-ups, Type-II buildings and bachelor barracks in 67 remote administrative headquarters.
		Prisons	10.00	To cover the requirement of water supply for the district jail, construction of additional male and female wards of 50 inmates capacity and residential accommodation for staff at Itanagar and Tezu.
3	Assam	Police Housing	50.00	(i) Rs. 15 crore for Construction of junior staff quarters in hills/remote areas. (ii) Rs.35 crore for Construction of junior staff quarters in other areas.
		Police Training	50.00	(i) Rs. 25 crore for construction of Police Academy (ii) Rs.25 crore for setting up the Counter Insurgency and Jungle Warfare School.
4	Bihar	Police Training	206.00	To set up police academy at Rajgir to cater to Deputy Superintendent of police, Sub inspector and other ranks.
		Police Housing	106.00	Construction of lower subordinate quarters, barrack accommodation for constables and model police stations.
5	Chhattisgarh	Police Training	42.00	To increase the training capacity of police training schools and strengthening the upcoming Police Academy at Chandkhuri and Counter Terrorism and Jungle Warfare (CTJW) at Kanker.
		Police Housing	250.00	Construction of accommodation for police personnel, especially constables, head-

				constables & non-gazetted officers.
		Prison	150.00	Construction of two new prisons, strengthen central prisons and upgrade other existing prisons.
6	Gujarat	Police Training	215.00	Strengthening infrastructure in the four police training establishments.
7	Haryana	Police Training	100.00	Support for strengthening the infrastructure of the police Department to conduct more effective training programmes.
		Fire	100.00	Upgrading and adequately equipping the Fire Services Department to face emergencies.
8	Jharkhand	Police Training	73.00	(i) Rs. 14 crore for establishment of Jharkhand Police Academy. (ii) Rs. 29 crore for up gradation of the Jungle Warfare School. (iii) Rs. 30 crore for enhancing capacity of Constable Training School at Padma.
		Police Housing	225.00	Integrated police colonies to provide family accommodation to the police force posted in extremist affected areas.
9	Karnataka	Police Training	150.00	Setting up of range-level and district-level police training schools all over the state to create additional capacity for training its police personnel.
10	Kerala	Upgrading of Police Department	100.00	Providing Community Police Resources Centres, Tourist Protection and Police Assistance Centres, Senior Citizens Protection Schemes, Foreigner Facilitation Centres and construction of dormitories for policemen.
		Prison	154.00	Improving facilities in prison, providing vocational training to prisoners and installation of solar lighting system in the prisons.
11	Madhya Pradesh	Police Training	180.00	To upgrade five police training centres and to establish a new basic constable school at Sagar in line with the standards and norms of the Bureau of Police Research and Development.
12	Maharashtra	Police Training	223.00	Enhancing police training facilities through up-gradation of various police training schools, police academy and detective training schools.
		Prison	60.00	Up gradation of facilities and improvement in prison security.
13	Manipur	Police Training	84.00	Up-gradation of Manipur Police Training School (Pangei) to Manipur Police Training College (MPTC).
		Infrastructure for Police Station in Rural and Remote areas.	23.00	Setting up of nine new police stations to strengthen police infrastructure in remote and rural areas.

14	Meghalaya	Police Training	50.00	To Strengthen infrastructure for training police personnel by setting up the Meghalay Police Academy.
15	Mizoram	Prison	30.00	Assistance for completion of three new district jails and two sub-jails.
		Police	31.00	Construction of 24 police stations along with residential quarters and 15 outposts in the border areas.
		Fire	20.00	Building new fire stations to revamp the fire and emergency services.
16	Nagaland	Police Housing	100.00	Construction of Type – I units for lower functionaries in remote areas.
17	Orissa	Police Training	70.00	(i) Rs 20 crore for establishment of basic training school for civil police at Bryee, Jagpur District. (ii) Rs 30 crore for establishment of a basic training school for armed police at Burla, Sambalpur District. (iii) Rs. 20 crore for establishment of a new anti-extremist training school at Koraput/Rourkela.
		Prison	100.00	Up gradation of security of jails in view of the extremist problem and ensuring better amenities to prisoners such as improvement in sanitation, water supply and medical care.
		Fire	150.00	Provision of fire services, State should ensure that part of this fund is utilized to upgrade the fire service training institutes and to provide training to fire service personnel.
18	Punjab	Police Training	200.00	Up gradation of training facilities for police personnel.
19	Rajasthan	Police Training	100.00	Strengthening of training infrastructure for police, jails, home guards and civil defence.
20	Sikkim	Police Training	10.00	Setting up of police training centre at Yangang to augment training capacity, including additional residential accommodation and equipment.
		Police Housing	15.00	Construction of residential and non-residential buildings for police force.
21	Tamil Nadu	Police Training	100.00	Strengthening of infrastructure facilities.
22	Tripura	Police Training	10.00	To establish a police academy.
		Construction of battalion headquarters for Tripura State Rifles.	75.00	Administrative blocks, barracks and staff quarters and other buildings for these battalions.
		Prison	15.00	Completion of second phase of the central jail at Bishalgar comprising construction of staff

				quarters, additional wards and a playground.
		Fire	15.00	Construction of headquarters of fire services.
23	Uttar Pradesh	Police Training	132.00	Strengthening of the present training infrastructure and setting up of new police training centres.
		Police Housing	200.00	Construction of residential buildings for non-gazetted police officers.
		Fire	20.00	Up gradation of fire and emergency services in Varanasi.
24	Uttarakhand	Police Training	70.00	(i) Rs. 20 crore for construction of Police Training centre. (ii) Rs 50 crore for construction of police stations and police outposts.
25	West Bengal	Police Training	163.00	(i) Rs 91 crore for augmentation of training capacity involving creation of training schools for 1600 additional personnel annually. (ii) Rs72 crore for Subsidiary Police Training Schools for the Kolkata police to ramp up training facilities for 1500 additional personally annually.
		Police Housing	90.00	Construction of 2000 units of residential accommodation for West Bengal and Kolkata police.
		Fire	150.00	To fill the infrastructure and equipment gaps in the West Bengal Fire and Emergency Department.
	Grand Total		Rs.4757cr	

Police Housing/Training/Up-gradation = Rs. 3676crore

Prison = Rs. 609crore

Fire Services = Rs. 472cr

Total = Rs 4757 crore

Grants recommended by Thirteenth Finance Commission (FC-XIII) for development of Border Areas (Line Ministry – Ministry of Home Affairs (MHA))

Review Committee chaired by Secretary (Border Management), MHA

(Rs in Crore)

Sl. No.	Name of State	Amount	Brief of Scheme
1	Arunachal Pradesh	25.00	Infrastructure development in Twang District to improve sanitation, drainage system, porter tracks, roads and housing in remote blocks of the district situated along the international border.
2	Assam	230.00	To provide basic facilities of water supply, roads & bridges and electrification along the international border area.
3	Gujarat	100.00	Construction of roads in the areas along the international border.
4	Himachal Pradesh	50.00	(i) Rs. 25 crore for construction of roads & bridges in Kalpa, Pooh and Spiti border blocks to provide alternative road links at the times of heavy snowfall. (ii) Rs 25 crore for strengthening of electricity infrastructure in the border areas of Kinnaur & Lahaul-Spiti to reduce dependence on fuel woods.
5	Jammu & Kashmir	35.00	(i) Rs. 20 crore for Upgradation of existing roads and new road connectivity in the remote areas of Kargil District. (ii) Rs. 15 crore for construction of bridges to improve the road connectivity.
6	Manipur	25.00	Improvement and up gradation of internal roads, sewerage and drainage, water, street lighting and basic urban amenities at Moreh at international border.
7	Nagaland	35.00	To develop roads and to provide clean drinking water in the border areas.
8	Punjab	250.00	Upgrade power, road connectivity, health infrastructure, water supply & sanitation in area along the international border.
9	Rajasthan	100.00	Strengthening of drinking water infrastructure in the border districts.
10	Sikkim	21.00	(i) Rs 6 crore to create additional storage facilities for essential commodities. (ii) Rs15 crore to improve the existing security infrastructure by creating check posts, road transport links and strengthening security equipments in the border area.

11	Uttar Pradesh	250.00	To develop roads along the international border for improvement in connectivity and rapid development.
12	Uttarakhand	105.00	Community development-cum-marketing centres and residential buildings for the Gram Vikas Adhikari and Agricultural Assistant in each Naya Panchayat of the five border districts.
13	West Bengal	150.00	Construction of roads in Border areas.
	Grand Total	Rs. 1376cr	

Grants recommended by Thirteenth Finance Commission (FC-XIII) for Health services and strengthening of health infrastructure during 2011-15 (Line Ministry – Ministry of Health and Family Welfare (MoH&FW))

Review Committee chaired by Secretary (Health), MoH&FW

(Rs in Crore)

Sl. No.	Name of State	Amount	Brief of Scheme
1	Andhra Pradesh	200.00	To fill the gap in Primary Health Centres and create the necessary facilities for improved provision of rapid, qualitative health and medical services especially, by setting up new PHCs in rural areas.
2	Arunachal Pradesh	50.00	To improve the physical infrastructure in Community Health Centres (CHCs), Public Health Centres (PHCs) and sub-centres in the state.
3	Chhattisgarh	66.00	For construction of 500 sub-health centres, 25 Primary Health Centres, 5 Community Health Centres (CHCs) and 100 Ayush Dispensaries with the provision that priority would be given to remote tribal areas.
4	Gujarat	237.00	Integrated quality services through public health schemes.
5	Haryana	300.00	(i) Rs 200 crore to strengthen the health infrastructure including additional PHCs, CHCs, Sub Division and district hospitals, to fill the gaps not covered under other ongoing programmes. (ii) Rs. 100 crore for setting up of medical college at Mewat.
6	Kerala	198.00	Improve the health infrastructure.
7	Madhya Pradesh	296.00	(i) Rs. 250 crore to improve the critical health infrastructure. (ii) Rs. 24 crore to establish Virology Laboratory at Gandhi Medical College, Bhopal. (iii) Rs. 22 crore to upgrade MTH Hospital, Indore.
8	Maharashtra	32.00	Setting up of food testing laboratories at six divisional headquarters.
9	Mizoram	30.00	For construction of 15 PHCs and 150 sub-centres along with staff quarters.
10	Nagaland	30.00	Construction of staff quarters for PHCs and sub-centres in rural areas.
11	Orissa	350.00	(i) Rs 275 crore to fill the gaps in buildings and staff quarters for sub-centres and PHCs with the proviso that the State makes a concerted effort to fill all gaps in the tribal districts. (ii) Rs. 75.00 crore for additional buildings in the three existing medical colleges.
12	Rajasthan	150.00	Strengthening infrastructure in public hospitals including diagnostic equipments and generators.
13	Tamil Nadu	200.00	To provide infrastructure in public hospitals including construction of health centres and water analysis laboratories and purchase of diagnostic equipments.
14	Uttarakhand	100.00	Establishment of five nursing colleges in Pithoragrah, Almora, Tehri, Chamoli and Pauri to address the issue of acute shortage of nursing staff in remote areas.
15	West Bengal	300.00	Construction of sub-centres, primary health centres and additions to the sub-divisional and district hospitals in the state.
	Grand Total	Rs. 2539cr	

Grants recommended by Thirteenth Finance Commission (FC-XIII) for Heritage and Culture during 2011-15 (Line Ministry – D/o Culture)

Review Committee chaired by Secretary, Department of Culture

(Rs in Crore)

Sl. No.	Name of State	Sector	Amount	Brief of Scheme
1	Andhra Pradesh	Culture	60.00	(i) Rs. 40 crore to preserve, protect and propagate the composite culture of India. (ii) Rs. 20 crore for establishment of 'Shilparamam' at Vijayawada, Nellore, Anantpur and Warangal.
		Heritage	100.00	For conservation, restoration and preservation of 560 protected ancient sites & historical monuments and for improvement modernization of its museums.
2	Arunachal Pradesh	Heritage	10.00	Preservation and development of various archaeological and historical sites.
3	Assam	Heritage	40.00	(i) Rs. 35 crore for construction as well as protection and maintenance of archaeological sites and monuments (ii) Rs. 5 crore for protection, preservation and promotion of the Satras of Majuli Island.
4	Bihar	Heritage	100.00	(i) Rs. 50 crore for creation of Nalanda Heritage Zone involving Buddhist institutions and establishment-linkages with other prominent location lying along the Buddhist trail (ii) Rs. 50 crore for development & conservation of 29 sites identified by the State Government.
5	Chhattisgarh	Heritage	45.00	For conservation works in monuments and other related activities such as training and publications.
6	Jammu & Kashmir	Heritage	50.00	Conservation and restoration of cultural heritage of Mubarak Mandi, Jammu.
7	Jharkhand	Heritage	100.00	To construct heritage galleries for the benefit of tourists as well as the local people.
8	Karnataka	Heritage	100.00	To protect the large number of heritage monuments and buildings reflecting the state's heritage.
9	Madhya Pradesh	Heritage	175.00	Conservation, development and management of heritage sites including three world heritage sites. Priority may be given to the large number of monuments which have not received any funds so far.
10	Maharashtra	Heritage	100.00	To protect and conserve various sites including forts and monuments which are under the care of state govt.
11	Manipur	Culture	8.00	Development and maintenance of Kangla Fort.
12	Meghalaya	Heritage	25.00	For protection, preservation and development of heritage sites, museums and buildings, including survey, research and documentation activities.
13	Mizoram	Heritage	12.00	Transforming the residence of the late chief of Hliappui village, hand over to the government, into a heritage centre by construction of an auditorium and public library in the vicinity of the building, and to improve the connectivity to the existing heritage places which are

				located at some distance from the village or main road
14	Orissa	Heritage	65.00	Conservation of heritage structures including a large number of Buddhists heritage sites.
15	Punjab	Heritage	100.00	Protection and maintenance of historical monuments and archaeological sites.
16	Sikkim	Heritage	9.00	Conservation of the remaining monuments not covered by the 12 FC grant.
17	Tamil Nadu	Heritage	100.00	Renovation and maintenance of ancient temples of historical importance, which reflect the state's heritage.
18	Tripura	Culture	10.00	For development of Kok-Borok language to preserve the linguistic identity of the Tripura tribes.
19	Uttar Pradesh	Heritage	100.00	Development of museums, conservation of monuments as well as strengthening of roads connecting important heritage sites.
20	Uttarakhand	Culture	45.00	(i) Rs. 25 crore for construction of state level museum. (ii) Rs.20 crore for auditorium for various cultural activities.
21	West Bengal	Heritage	100.00	Maintenance of numerous historical monuments, museums, archives and archaeological sites.
	Grand Total		Rs.1454 cr	

Culture = Rs. 123.00 cr,

Heritage = Rs. 1331 cr.

Total = Rs. 1454 cr.

**Grants Recommended by Thirteenth Finance Commission (FC-XIII) for Irrigation
(Line Ministry – Ministry of Water Resources)**

Review Committee chaired by Secretary, Ministry of Water Resources

(Rs in Crore)

Sl. No.	Name of State	Amount	Brief of Scheme
1	Bihar	333.00	Interlinking of Burhi Gandak – None-Baya-Ganga rivers to reduce damages due to floods in Samastipur, Begusarai and Khagaria districts after obtaining necessary clearance.
2	Gujarat	200.00	To recharge ground water, construction of check dams, cleaning and restoration of step wells, deepening of wells and rain water harvesting in North Gujarat and Saurashtra.
3	Karnataka	350.00	Rehabilitate more than 30,000 minor irrigation tanks which are not covered under the existing rehabilitation projects.
4	Kerala	50.00	Restoration of tanks through desilting, repairing sluices and constructing retaining structures.
5	Punjab	650.00	(i) Rs.200 crore to upgrade the irrigation infrastructure. (ii) Rs.200 crore to address the problems in water-logged areas. (iii) Rs. 250 crore for soil conservation and water harvesting for development of Kandi areas.
6	Rajasthan	300.00	To complete the 60 pending irrigation projects, which could be completed within next three years.
7	Uttar Pradesh	200.00	Drought proofing and strengthening of irrigation facilities in the Bundelkhand region by strengthen and restore tanks, build check dams and refurbish tube wells.
8	West Bengal	450.00	Strengthening of embankments, construction and renovation of drainage structures in the Sunderban region to prevent damage from tidal floods.
	Total	Rs.2533 cr	

Grants recommended by the Thirteenth Finance Commission (FC-XIII) for Anganwadi Centres (Line Ministry – M/o.Women & Child Development)

Review Committee chaired by Secretary, Ministry of Women and Child Development
(Rs. in crore)

Sl. No.	Name of State	Amount	Brief of Scheme
1	Chhattisgarh	150.00	Construction of anganwadi bhawans.
2	Jharkhand	432.00	Construction of 10000 anganwadi centres.
3	Madhya Pradesh	400.00	Construction of anganwadi centres Priority may be given to areas with high proportion of tribal and SC population as well as other areas with high rates of malnutrition.
4	Maharashtra	300.00	Construction of new buildings for anganwadi centres.
5	Orissa	400.00	Construction of anganwadi centres with priority to the tribal areas of the state.
6	Punjab	250.00	To support for various programmes to improve the adverse sex ratio in the state
6	West Bengal	300.00	Construction of anganwadi centres.
	Total	Rs. 2232 cr	